

(f) whether Government have ensured smooth supply of spare parts for them and how these computers are being utilised ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) Yes, Sir, Computer made by Osborne were imported in past. However, Government is not aware of any problems due to non availability of spare parts for these computer systems.

(b) One such computer have been cleared by DOE for import between 1981-84. This computer is of US origin. The cost of this computer US \$ 2200 00 (CIF). As this computer system was imported by an Educational institution no customs duty has been paid on it.

(c) The Government has imported computers made by Acorn for a pilot project of computer literacy in schools. Government has no plans to import Apple computers.

(d) Under the pilot project of the school literacy programme (CLASS), Department of Electronics has imported 170 micro computers from Acorn, U.K. and is planning to import another 730 computer systems from the same party.

(e) As these items are for educational purposes, the project have been exempted from the payment of customs duty. The micro computers for the pilot project are being arranged under the bilateral technical cooperation programme between Indian and U.K. The Government of U.K. accordingly has agreed to supply the computers required for this programme and hence no tenders were invited for this purpose.

(f) Government has ensured smooth supply of spare parts for these computer systems by an arrangement between the Computer Maintenance Corporation (CMC) and the Acorn, U.K. for conti-

nued support. These computers will be used for educational purposes and to increase the awareness of computers among the school children.

सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4171. श्री लाला राम केन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण किया गया है ;

(ख) क्या कुछ सरकारी विभागों में प्रशासनिक अधिकारियों ने उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अभी तक उचित आरक्षण प्रदान नहीं किया है ; तथा इस प्रकार आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के पद घोषित करके भर दिया जाता है ; और

(ग) इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि किसी भी स्थिति में आरक्षित पदों का सामान्य श्रेणी के पद घोषित नहीं किया जाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम बुलारी सिन्हा) : (क) भारत सरकार के अधीन पदों/सिवाशों में रिक्तियों के भरे जाने के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है ।

(ख) और (ग) सरकार के अधीन सभी प्रशासनिक कार्यालयों (उन कार्यालयों को छोड़कर जिन्हें इस प्रयोजन से विशिष्ट छूट दी गई है) में अपेक्षा की जाती है कि

वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करें, किन्तु जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाते वहां आरक्षित रिक्तियां प्रनारक्षित कर दी जाए और इन्हें यदि आवश्यक हो, तो लोकहित में सामान्य प्रवर्गों के उम्मीदवारों में से भरा जाए। किन्तु इन सभी मामलों में, समूह "ग" से समूह "ख", समूह "ख" के भीतर और समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी तक चयन द्वारा पदोन्नति को छोड़कर, ऐसे आरक्षणों को तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत करना होता है।

#### Immigrants from Bangladesh

4172. SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY : Will the Minister of HOME

AFFAIRS be pleased to state :

(a) total number of immigrants entered into India from Bangladesh during the year 1981, 1982 and 1983 and upto the month of June 1984 ;

(b) whether Government have any information of the number of such people entering into different border States from Bangladesh ; and

(c) whether any assurance has been received from Bangladesh to prevent such entrants ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) and (b) The number of Bangladeshis who entered India on short term and long term visas during the years 1981 to 1983, state-wise is given below :—

Year	States			Total
	Assam	West Bengal	Tripura	
1981	683	193135	538	194457
1982	1455	196769	643	199073
1983	1393	203866	489	205978

Figures for the Year 1984 are not available.

These figures also do not include Bangladeshis who came to India by air.

(c) No, Sir.

पंजाब में विदेशी राष्ट्रियों का प्रवेश

4173. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कानपुर से प्रकाशित दिनांक 26 जून, 1984 के जागरण में "दिल्ली से अमृतसर जाने वाले फ्रांसिसी

कीन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के अनुमान के अनुसार जब पंजाब में केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश वर्जित था, तो उस अवधि के दौरान कितने विदेशी राष्ट्रियों ने पंजाब में प्रवेश किया था ;

(ग) क्या इसमें टैक्सी ड्राइवर्स का एक